

न्यायमूर्तिगण आई.एस. तिवाना और अमरजीत चौधरी, के समक्ष

के.के. वैद,—याचिकाकर्ता ,

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1986 का सिविल रिट याचिका संख्या. 4180

1 नवंबर,

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II और नियम 3.26(डी) -हरियाणा सरकार के निर्देश दिनांक 13 अगस्त, 1983 -नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष -सरकारी निर्देश 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद विस्तार प्रदान करते हैं - विस्तार के लिए मानदंड निर्धारित -ऐसे मानदंडों के लिए 70 प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है -की वैधता ऐसे मापदण्ड—सार्वजनिक हित—का अर्थ है।

अभिनिर्धारित किया कि यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित को अभी तक कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, अब तक सेवा के संबंध में यह एक निश्चित अवधारणा या अर्थ प्राप्त कर चुका है। मामले चिंतित हैं. इस संबंध में परीक्षण यह है कि क्या जिस कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त किया जाना है, वह बेकार है या ड्रोन या कुछ भी नहीं करने वाला कर्मचारी है। उपर्युक्त नियम के खंड (डी) में दर्ज इस परीक्षण या सार्वजनिक हित की अवधारणा के प्रकाश में, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्देशों में निर्धारित मानदंड केवल 70 प्रतिशत से अधिक वाले अधिकारी को "अच्छा या ऊपर" मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने का अधिकार इस नियम की भावना के बिल्कुल विपरीत है। इन निर्देशों की अभिव्यक्ति की सरलता और उनके दायरे की व्यापकता बस चौंकाने वाली है। इन निर्देशों के अनुसार कर्मचारी की सेवा में बने रहने की वांछनीयता के बजाय सेवा में बने रहने के लिए उसकी सकारात्मक योग्यता पर जोर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह दृष्टिकोण पूरी तरह से भ्रामक है और स्पष्ट रूप से 'मृत लकड़ी' के परीक्षण के विपरीत है। केवल इतना ही, ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्देश किसी सरकारी कर्मचारी के कार्यकाल या सेवा अवधि के बारे में एक गलत धारणा के तहत जारी किए गए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, नियम 3.26 (ए) के तहत एक सरकारी कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, यानी उसे सामान्य रूप से तब तक सरकारी सेवा में बने रहना होगा। इस समय पर। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विवादित निर्देशों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकारी अधिकारी 55 वर्ष की आयु में एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति मानते हैं। यही कारण है कि निर्देश में लिखा है, "कर्मचारियों/अधिकारियों को 55 वर्ष की आयु से अधिक का विस्तार इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि पिछली दस गोपनीय रिपोर्टों में से 70 प्रतिशत से अधिक अच्छी या उससे ऊपर हों।" यह पूरी तरह से नियम 3.26(ए) के अक्षरशः और भावना के विपरीत है। इसलिए इन निर्देशों को इस नियम के उपबंधों (ए) और (डी) का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

(पैरा 6)

अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय: -

- (i) मामले के अभिलेख को प्रतिवादी से माँगावे ;
- (ii) सर्विओरारी रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो मविवादित आदेश 'पी / 5 ' को रद्द करदे;
- (iii) मैडमस रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो प्रतिवादी को उक्त आदेश ( पी / 5 ) को सभी परिणामी मौद्रिक लाभों के साथ सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नोन-एस्ट मानने के लिए जारी की जाये;
- (iv) याचिकाकर्ता को देय वेतन और भत्तों के बकाया पर हजनि के रूप में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की बाजार दर पर ब्याज की अनुमति दें, जो वार्षिक रूप से संयोजित होगा;

I.L.R. Punjab and Haryana (1991)1

- (v) कोई अन्य राहत प्रदान करें जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे ;
- (vi) जिन दस्तावेजों की सच्ची प्रतियां संलग्न की गई हैं, उनकी मूल / प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट ;
- (vii) प्रतिवादी को अग्रिम सूचना देने से छूट ;
- (viii) इस रिट याचिका की लागत का पुरस्कार दें।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान , विवादित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जा सकती है।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता गुरदीप सिंह के साथ के. के. जगिया, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी की ओर से मदन देव, अधिवक्ता ।

निर्णय

1. न्यायमूर्ति एस. तिवाना,

(1) यह मामला मुख्य रूप से हरियाणा सरकार के निर्देशों दिनांकित 13 अगस्त 1983 (याचिका का अनुलग्नक पी-3) की अधिकार या वैधता को आंकने के संदर्भ में है।

K. K. Vaid v. State of Harvana (I. S. Tiwana, J.)

ये निर्देश इस प्रकार हैं:-

“विषय: 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में एक्सटेंशन 55 वर्ष की आयु के बाद एक्सटेंशन देने की नीति में बदलाव।

...

...

...

मामले पर पुनर्विचार करने के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 55 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को इस शर्त के साथ सेवा विस्तार दिया जा सकता है कि पिछली 10 गोपनीय रिपोर्टों में से 70 प्रतिशत से अधिक अच्छी या उससे अधिक हों।

राजपत्रित अधिकारियों के मामले में

औसत रिपोर्ट से अधिकारियों को अवगत कराया जाए और यदि ऐसी रिपोर्ट के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन छह माह के भीतर प्राप्त होता है तो उस पर आवश्यक निर्णय लिया जाए।

(2) जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष मामला शुरू में सुनवाई के लिए आया था, की राय थी कि इसमें शामिल प्रश्न बड़ी संख्या में कर्मचारियों के भाग्य को नियंत्रित करने की संभावना है और इस न्यायालय में बड़ी संख्या में इसी तरह के मामले लंबित हैं, यह सार्थक है कि प्रश्न का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। इस तरह से हम मामले को जब्त कर लेते हैं।

(3) पक्षकारों द्वारा उठाए गए संबंधित तर्कों की सराहना करने के लिए, निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है: -

याचिकाकर्ता समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया है, -*आक्षेपित* आदेश अनुलमक पी.5 के अनुसार। जो की निम्न प्रकार से है: -

“जबकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि श्री कृष्ण कुमार वैद, उपमंडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) हरियाणा, को उसके 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाये!

इसलिए, अब, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32-ए(सी) और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 3.26(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, जैसा कि लागू है के कर्मचारी

I.L.R. Punjab and Haryana (1991)1

हरियाणा राज्य, हरियाणा के राज्यपाल, जनहित में, आदेश देते हैं कि श्री कृष्ण कुमार वैद, उपमंडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा, हरियाणा तीन महीने की समाप्ति पर हरियाणा राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस नोटिस के जारी होने की तारीख.

(एमसी गुप्ता),  
वित्तीय आयुक्त एवं

Dated Chandigarh  
the 17th July, 1986.

सचिव, सरकार। हरियाणा  
सिंचाई विभाग।”

(4) प्रतिवादी प्राधिकारियों के लिए यह स्पष्ट मामला है (लिखित बयान के अनुसार) कि याचिकाकर्ता को आदेश में उल्लिखित नियमों और सरकारी निर्देशों अनुलग्नक पी.3 के अनुसार सेवानिवृत्त कर दिया गया है। उनका सटीक रुख यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड अनुबंध पी.3 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था, इसलिए उनके पास उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे शब्दों में, रुख यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने सेवा करियर के पिछले दस वर्षों के दौरान 70 प्रतिशत 'अच्छी या उससे ऊपर' गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करने में विफल रहा, इसलिए उसे सार्वजनिक हित में बाहर करना पड़ा। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि सरकारी निर्देशों में निहित उपर्युक्त मानदंड न केवल पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I के नियम 3.26 (डी) में निर्धारित परीक्षण का उल्लंघन है। लेकिन इन नियमों के 3.26(ए) के साथ सीधे टकराव में भी है। आगे बढ़ने से पहले इन प्रावधानों की सामग्री पर ध्यान देना और याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड की बैलेंस शीट पर नज़र डालना उचित प्रतीत होता है जैसा कि लिखित बयान में ही बताया गया है। नियम 3.26 के खंड (ए) और (डी) की प्रासंगिक सामग्री इस प्रकार है: -

“3.26 (ए) इस नियम के अन्य खंडों में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें वह अट्ठाईस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए:

(डी) नियुक्ति प्राधिकारी को, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन का नोटिस देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे नोटिस के बदले लिखित रूप में तीन महीने या तीन महीने का वेतन और भत्ते: -

“(i) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी सेवा या पद पर है और उसने पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकारी सेवा में प्रवेश किया था; और

(11) (ए) यदि वह तृतीय श्रेणी सेवा या पद पर है, या

(बी) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश किया है;

पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।”

**K. K. Vaid v. State of Harvana (I. S. Tiwana. J.)**

(5) विचाराधीन आदेश में पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32-ए (सी) का भी संदर्भ दिया गया है, फिर भी न तो यह दलील दी गई है और न ही किसी भी तरीके से दिखाया गया है कि इस नियम का पालन करते समय इस नियम का अनुपालन किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई इसलिए, इस नियम का विस्तृत पुनरुत्पादन आवश्यक नहीं है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 1983 (प्रतिलिपि अनुलग्नक आरएल) के तहत, इस नियम के खंड (बी) के तहत नोट को टीवी/ओ नोट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था / जबकि नोट (1) राज्य सरकार को बिना कोई कारण बताए पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है, लेकिन अक्षमता, बेईमानी, भ्रष्टाचार या कुख्यात आचरण के कारण, नोट (2) ने इसे अनिवार्य बना दिया है। सरकार को "प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर" देना होगा और "मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना" कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं करना होगा जैसा कि पहले बताया गया है, यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि या तो याचिकाकर्ता नोट (1) में निर्दिष्ट किसी भी कदाचार का दोषी था या नोट (2) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था। इसलिए, यह नियम किसी भी तरह से याचिकाकर्ता की आक्षेपित सेवानिवृत्ति को कायम नहीं रखता है।

1)1

याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड का उद्धरण इस प्रकार है: -

श्री. क्रमांक रिपोर्ट का वर्ष/अवधि।	वर्ग
1. 1 अप्रैल, 1975 से 19 जुलाई, 1975	औसत।
29 जुलाई, 1975 से 31 जुलाई तक मार्च, 1976	अच्छा।
2. 1 मई, 1976 से 4 अगस्त तक, 1976	निलंबनाधीन.
5 अगस्त, 1976 से 4 अगस्त तक जनवरी, 1977	औसत।
5 जनवरी, 1977 से 31 जनवरी तक मार्च, 1977	एक छोटी सी अवधि में।
3. 1 अप्रैल 1977 से 10 तक अक्टूबर, 1977	अच्छा।
18 अक्टूबर, 1977 से 31 अक्टूबर तक	अच्छा।
मार्च, 1978	एक छोटी सी अवधि में।
4. 1 अप्रैल, 1978 से 17 जून, 1978	अच्छा।
18 जून. 1978 से 31 तक मार्च, 1979	अच्छा।
5. 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980	अच्छा।
6. 1 अप्रैल. 1980 से 31 मार्च, 1981	औसत।
7. 1 अप्रैल 1981 से 15 तक दिसंबर, 1981	औसत।
16 दिसम्बर, 1981 से 31 दिसम्बर तक	अच्छा।
मार्च, 1982	

K. K. Vaid v. State of Harvana (I. S. Tiwana. J.)	
8. 1 अप्रैल, 1982 से 23 तारीख तक	नहीं पाना।
अगस्त, 1982	
24 अगस्त, 1982 से 31 अगस्त तक	औसत।
मार्च, 1983	
9. 1 अप्रैल, 1983 से 2 जून, 1983	एक छोटी सी अवधि में।
3 जून, 1983 से 21 जुलाई, 1983	एक छोटी सी अवधि में।
22 जुलाई, 1983 से 17 जुलाई तक	एक छोटी सी अवधि में।
अगस्त, 1983	
18 अगस्त, 1983 से 21 अगस्त तक	प्रतीक्षा अवधि।
मार्च, 1984	
10. 30 मई, 1984 से 31 मई तक	अच्छा।
मार्च, 1985	

---

(6) नियम 3.26(ए) के खंड (ए) के खंड (ए) में संदर्भित 7ए स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सामान्य तौर पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होना होता है, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसे पहले यानी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त करने की राय बनाता है जैसा कि याचिकाकर्ता के मामले में किया गया है। यह राय स्पष्ट रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टिपूर्ण गुट नहीं है, बल्कि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक है। दूसरे शब्दों में, राय व्यक्तिगत, राजनीतिक या सार्वजनिक हित को छोड़कर किसी अन्य हित पर आधारित नहीं हो सकती, यानी सेवा के हित में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के परिणामस्वरूप अब तक सार्वजनिक हित को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, अब तक सेवा के संबंध में यह एक निश्चित अवधारणा या अर्थ प्राप्त कर चुका है। मामले चिंतित हैं। हमें अंतिम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के इन सभी निर्णयों का संदर्भ देना पूरी तरह से अनावश्यक लगता है, सिवाय इसके कि इस संबंध में परीक्षण यह है कि क्या समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी मृत लकड़ी या ड्रोन है या कुछ न करने वाला कर्मचारी। यह निष्कर्ष हम अंतिम न्यायालय की घोषणाओं से प्राप्त करते हैं जैसा कि *भारत संघ बनाम जेएन सिन्हा और अन्य*, (1) और *बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ और अन्य*, (2) में दर्ज किया गया है। उपर्युक्त नियम के खंड (डी) में दर्ज इस परीक्षण या सार्वजनिक हित की अवधारणा के प्रकाश में, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्देशों में निर्धारित मानदंड केवल 70 प्रतिशत से अधिक वाले अधिकारी को "अच्छा या ऊपर" मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने का अधिकार इस नियम की भावना के बिल्कुल विपरीत है। इन निर्देशों की अभिव्यक्ति की सरलता और उनके दायरे की व्यापकता बेहद चौकाने वाली है। इन निर्देशों के अनुसार कर्मचारी की सेवा में बने रहने की वांछनीयता के बजाय सेवा में बने रहने के लिए उसकी सकारात्मक योग्यता पर जोर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह दृष्टिकोण पूरी तरह से भ्रामक और 'मृत लकड़ी' के परीक्षण के बिल्कुल विपरीत है। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्देश किसी सरकारी कर्मचारी के कार्यकाल या सेवा अवधि के बारे में गलत धारणा के तहत जारी किए गए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, नियम 3.26 (ए) के तहत एक सरकारी कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, यानी, उसे सामान्य रूप से तब तक सरकारी सेवा में बने रहना होगा उस समय।

(1) एआईआर 1971 एससी 40।

(2) 1980(3) एसएलआर 1.

पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकारी अधिकारी 55 वर्ष की आयु में एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति मानते हैं। यही कारण है कि निर्देशों में दर्ज है, "कर्मचारियों/अधिकारियों को 55 वर्ष की आयु से अधिक का विस्तार इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि पिछली दस गोपनीय रिपोर्टों में से 70 प्रतिशत से अधिक अच्छी या उससे ऊपर हों।" यह पूरी तरह से नियम 3.26(ए) के अक्षरशः और भावना के विपरीत है। इसलिए इन निर्देशों को इस नियम के खंड (ए) और (डी) का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

(7) आक्षेपित आदेश परिशिष्ट पी. 5 भी मनमानी से ग्रस्त प्रतीत होता है। यह समझ से परे है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड में औसत प्रविष्टि को कैसे और क्यों अपने प्रतिकूल मान लेती है। "औसत" शब्द का मतलब मध्यम या सामान्य से अधिक कुछ नहीं है। किसी कर्मचारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए उसके सेवा रिकार्ड की जांच करते समय तीन स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। वह सकारात्मक रूप से अच्छा या सकारात्मक रूप से बुरा हो सकता है और न तो अच्छा हो सकता है और न ही बुरा। यह केवल अंतिम श्रेणी है जिसे औसत आयु के रूप में मूल्यांकित या मूल्यांकन किया जा सकता है। हालाँकि इन निर्देशों के आलोक में यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हरियाणा सरकार अपने सभी कर्मचारियों से न केवल औसत से ऊपर होने की उम्मीद करती है, बल्कि कुछ और भी, यानी अच्छा या ऊपर, फिर भी औसत प्रविष्टि को बनाए रखना मुश्किल लगता है। इसे प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में लिया जाना चाहिए। यह केवल उन कर्मचारियों के मामले में है जो सकारात्मक



रूप से खराब हैं, ऊपर उल्लिखित नियम 3.26 के खंड (डी) के संदर्भ में सरकार द्वारा उन्हें कम उम्र में सेवानिवृत्त करना उचित हो सकता है। यह दर्ज करने के लिए कि एक औसत प्रविष्टि को संभवतः प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में नहीं माना जा सकता है, हम कम से कम तीन निर्णयों से समर्थन चाहते हैं - शीर्ष न्यायालय के दो और इस न्यायालय के तीसरे, यानी, बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ और अन्य, एचसी गार्गी बनाम हरियाणा राज्य, (3) और हंस राज पुरी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (4)। बाद के दो निर्णय उसी नियम से संबंधित हैं जिसकी हमने ऊपर जांच की है, यानी, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I का 3.26।

(8) उपरोक्त सभी बातों के अलावा, हम पाते हैं कि विवादित आदेश, अनुबंध पी. 5, दो कमजोरियों से ग्रस्त है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता की पहली दो औसत रिपोर्टें - यदि इन्हें प्रतिकूल रिपोर्ट के रूप में लिया जाए - (i) 1 अप्रैल, 1975 से 19 जुलाई, 1975 और (ii) 5 अगस्त, 1976 से

(3) 1986(3) एसएलआर57.

(4) 1989 लैब. आईसी 1310.



K. K. Vaid v. State of Harvana (I. S. Tiwana, J.)

4 जनवरी 1977, उन्हें कभी नहीं बताया गया। क्रमांक 6, 7 और 8 की अन्य तीन रिपोर्टों के संबंध में, ये निश्चित रूप से उन्हें बताई गई थीं और उन्होंने इसके खिलाफ विधिवत प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इन अभ्यावेदनों का अंततः 16 सितंबर, 1988 को निपटारा कर दिया गया; क्रमशः 29 नवंबर, 1988 और 1 अप्रैल, 1987। संक्षेप में, जब आक्षेपित आदेश अनुलमक पी.5 बनाम पारित हुआ, तब तक इन अभ्यावेदनों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था और वे विचाराधीन थे। *बृज मोहन चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य मामले* में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य की टिप्पणियों के आलोक में, (5) एक सरकारी कर्मचारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश संभवतः उन प्रतिकूल प्रविष्टियों पर आधारित नहीं हो सकता है जिनके बारे में सूचित नहीं किया गया है। उसे या, यदि सूचित किया जाता है, तो उन प्रविष्टियों के विरुद्ध किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है और उनका निपटान नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार दी राय:-

“ये निर्णय इस सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि जब तक कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संप्रेषित नहीं की जाती है और कर्मचारी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति से इनकार करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हमारी राय है कि यही विचार उस मामले पर भी लागू होना चाहिए जहां किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त करने में प्रतिकूल प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाता है। किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त करना अन्यायपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा, जिसके बारे में या तो उसे सूचित नहीं किया जाता है या यदि सूचित किया जाता है, तो उन प्रविष्टियों के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है और उनका निपटान नहीं किया जाता है।”

(9) इसके बाद उत्तरदाताओं का यह स्वीकार किया गया मामला है (लिखित बयान का पैरा 6) कि याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल 1979 से अपने सेवा रिकॉर्ड के आलोक में दक्षता बाधा को पार करने की अनुमति दी गई थी - आदेश दिनांक 8 मई 1981 के तहत इस प्रकार यह पेटेंट है कि 1 अप्रैल, 1979 से पहले के सेवा रिकॉर्ड या किसी भी तथ्याकथित प्रतिकूल प्रविष्टि को अप्रासंगिक बना दिया गया था और विवादित आदेश अनुलमक पी 5 पारित करते समय उस पर विचार नहीं किया जा सका। इसलिए, आदेश खराब है इस स्कोर पर भी.

(10) इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि न केवल विवादित निर्देश, एनेक्चोर पी. 3 ऊपर उल्लिखित नियम का उल्लंघन हैं बल्कि

**(5) एआईआर 1987 एससी 948।**

आक्षेपित आदेश, अनुलमक पी. 5 को स्वयं मनमानी की सीमा से परे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचार, यानी, क्या यह सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित के अधीन थी, को प्रकाश में नजरअंदाज कर दिया गया था। निर्देशों के अनुलमक पी. 3 और इसके विपरीत अप्रचलित सामग्री, यानी 1 अप्रैल, 1979 से पहले का सेवा रिकॉर्ड, जिस तारीख से याचिकाकर्ता ने दक्षता बार पार किया था, उस पर विचार किया गया। आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निस्तारण न होने के कारण भी आदेश खराब है।

(11) इसलिए, हम आदेश अनुबंध पी.आईआर 51 को रद्द करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि याचिकाकर्ता सामान्य पाठ्यक्रम में सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में बना रहा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को इस आदेश के पारित होने से मिलने वाले वेतन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि के सभी लाभ दिए जाएंगे। उन्हें इस मुकदमे की लागत का भी हकदार माना जाता है, जिसका आकलन हम रुपये 1000 करते हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा।

एससीके

न्यायमूर्तिगण जी.सी. मीता और अमरजीत चौधरी, के समक्ष

फूड स्पेशलिटीज\* लिमिटेड, मोगा (पंजाब), -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य, - प्रतिवादीगण

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 6381

27 मार्च, 1990.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5) - अध्याय 4, शीर्षक 04.01 उप-शीर्षक 0401.13 और 0401.29 - आईएस 1 द्वारा जारी दूध पाउडर के लिए भारतीय मानक विशिष्टता ( आईएसएस) - सीएलएस। 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. और 3.2- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955- सीएल। 11, परिशिष्ट 'बी', उप सीएल।

11.01.10, 11.02.16 और 11.03 - याचिकाकर्ता विनिर्माण उत्पाद जिन्हें 'चाय और कॉफी के लिए नेस्ले एवरीडे डेली व्हाइटनर' के रूप में जाना जाता है - पैकिंग में सामग्री को 'आंशिक रूप से स्किमड दूध और सुक्रोज' के रूप में दिखाया गया है - उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है - आंशिक रूप से स्किमड दूध पाउडर और स्किमड मिल्क पाउडर - भेद - आंशिक रूप से स्किमड मिल्क पाउडर उप-शीर्ष 0.401.13 के तहत शुल्क के अधीन नहीं है - आइटम अवशिष्ट उप-शीर्ष 0401.19 के अंतर्गत आता है - शुल्क लगाना अवैध - वापसी का आदेश दिया गया।